P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-8* ISSUE-4* December- 2020
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में लघु एवं कुटीर उद्योगों का योगदान

Small and Cottage Industries Contribute to Uttar Pradesh's Economy

Paper Submission: 15/12/2020, Date of Acceptance: 25/12/2020, Date of Publication: 26/12/2020

मधुकर श्याम शुक्ला
सह प्राध्यापक,
विभागाध्यक्ष,
अर्थशास्त्र विभाग,
एस० एस० कॉलेज
शाहजहाँपुर उ०प्र० भारत

राम शंकर पाण्डेय
सहायक प्राध्यापक,
अर्थशास्त्र विभाग,
एस० एस० कॉलेज
शाहजहाँपुर उ०प्र० भारत

सारांश

निर्माण, रोजगार, और निर्यात क्षेत्र में सूक्ष्म और मध्यम उपक्रम का महत्वपूर्ण योगदान हैं। देश के कुल उत्पादन में इनकी 45 प्रतिशत और कुल निर्यात में इनकी 40 प्रतिशत हिस्सेदारी है। और इनमें लगभग 660 हजार लोगों को रोजगार प्राप्त हैं। उनकी सफलता में प्रौधोगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका है जब देश में उधोग पर्याप्त मात्रा में कार्यरत होते है तब देश में उच्च उत्पादकता होती है जोकि विकास प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। यह उद्योग आर्थिक शक्ति में केन्द्रीयकरण करके सम्पत्ति एवं आय की असमानताओं को कम करते है। सरकार बहुत सी योजनाओं के द्वारा इन उद्योगों को बढ़ावा दे रही है जिससे देश में बेरोजगारी कम की जा सके और नवयुवकों को रोजगार मिलें। देखना यह है कि सरकार के द्वारा चलायी जा रही योजनाओं से क्या प्रभाव पड़ रहा हैं।

Micro and medium enterprises contribute significantly to the construction, employment, and export sectors. They account for 45 percent of the country's total production and 40 percent of the total exports. And about 660 thousand people are employed in them. Technology has an important role in their success, when industries are employed in sufficient quantity in the country, then the country has high productivity which is an integral part of the development process. These industries reduce the inequalities of wealth and income by centralizing economic power. The government is promoting these industries through several schemes to reduce unemployment in the country and provide employment to the youth. It remains to be seen what are the effects of the schemes being run by the government.

मुख्य शब्द : निर्माण रोजगार, आयात, उत्पादकता, योजनाओं असमानताओं, बेरोजगारी खनिजों, आत्मनिर्भरता।
Construction Employment, Imports, Productivity, Planning Disparities, Unemployment Minerals, Self-Sufficiency.

प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश उद्योगों की दृष्टि से मध्यम श्रेणी का राज्य हैं। प्रदेश की लघु औद्योगिक इकाईयों के वृहद विकास के उधोग से उ० प्र० लघु उधोग निगम की स्थापना जून, 1958 में पूर्ण शासकीय स्वामित्वाधीन कम्पनी के रूप में हुई जिसका संकल्प भारत सरकार के M.S.M.E एक्ट 2006 में दोहराया गया है जिससे विकास की भागीदारी को बढ़ाया जा सकें। यहाँ खनिजों, सुविधाओं तथा निवेश की कमी के कारण उद्योगों का विकास कम हुआ कृषि आधारित तथा लघु एवं कुटीर उद्योगों का पर्याप्त विकास हुआ है। यहाँ उद्योगों की प्रकृति भिन्न –2 है जहाँ बड़े पैमाने के उद्योगों में पूँजी की अधिक आवश्यकता होती है वही लघु एवं कुटीर उद्योगों को ग्रामीण क्षेत्रों में सरलतापूर्वक अपनाया जा सकता हैं।

भारत सरकार ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम पारित कराया है जिसके अनुसार–(वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार)

1. एक करोड़ रु० से कम इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ रु० से कम टर्नओवर वाले सभी उधोग सूक्ष्म उद्योग होगें।
2. दस करोड़ रु० से कम इन्वेस्टमेन्ट और 50 करोड़ से कम टर्नओवर वाले सभी उद्योग लघु उधोग होगें।

3. 20 करोड़ रु० से कम इन्वेस्टमेन्ट और 100 करोड़ से कम टर्नओवर वाले सभी उद्योग मध्यम श्रेणी के उधोग होगें।

अध्ययन का उद्देश्य

लघु एवं कुटीर उद्योग के सम्बन्ध में शोध अध्ययन के मुख्य उद्देश्य निम्न होगेः–

1. अनेक प्रकार के कच्चे माल जैसे लोह एवं इस्पात, अलौह धातुएँ, कोयला आदि लघु इकाईयों को उपलब्ध कराने।
2. प्रदेश के अल्पविकसित स्थानों में सयुक्त क्षेत्र के अधीन अंश पूंजी में सहभागीदारी के अन्तर्गत उद्योगों की स्थापना कराना।
3. आयातित कच्चे माल एवं मशीनों की इकाईयों की विशिष्ट माँग पर आपूर्ति।
4. लघु उद्योगों को वित्त की उपलब्धता।
5. सरकार के द्वारा इस उद्योगों हेतु चलायी जा रही योजनाओ का अध्ययन करना।
6. ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लघु एवं कुटीर उद्योगों से कृषि, स्वास्थ्य, रोजगार, आत्मनिर्भरता तथा आर्थिक सामाजिक स्थिति का पता लगाना इस शोध पत्र का प्रमुख उद्देश्य हैं।

साहित्य का अवलोकन

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ केन्द्र सरकार के साथ मिलकर प्रदेश के निवासियों के लिए अनेक रोजगार परक योजनाओं जैसे– प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण सहायता योजना, मुद्रा योजना एवं अन्य M.S.M.I ऋृण शमिल है जिनसे प्रदेश निवासियों को रोजगार मिल रहा है। कारोनाकाल में भी प्रदेश सरकार ने 03 दिसम्बर 2020 को ऑनलाइन ऋृण मेले के अन्तर्गत साढ़े तीन लाख से ज्यादा कुटीर लघु एवं मझलें उद्योगों को 10 करोंड़ रूपये की धनराशि कर्ज के रूप में दी। एक जनपद एक उत्पाद के अन्तर्गत 5000 प्रशिक्षार्थियों को टूल किट ऑनलाइन दिये गये। प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के लघु एवं कुटीर उद्योग को आधुनिकरण हेतु सरकार हर सम्भव मदद करेगी प्रदेश सरकार ने केन्द्र की प्रंधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना को कैबिनेट में पास कर यिा गया जिसके अन्तर्गत अगले पांच साल तक प्रदेश के 37.805 छोटे एवं सूक्ष्म कुटीर उद्योग आधुनीकरण एवं ऊंच्चीकरण हेतु 10 लाख रूपये तक की सहायता दी जायेगी। ऐसी इकाईया जिनमें 10 व्यक्ति से कम कार्य करते है उन्हें तकनीकी सहायता प्रदान करके प्रदेश के प्रत्येक जिले में उसके उत्पाद को क्लस्टर बनाकर छोटे एवं सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा मिल सकें सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 1,70,123 लोगों को रोजगार मिलेगा यह योजना 2024–25 तक लागू रहेगी तथा कुल लागत का 33 फीसदी या 10 लाख रूपये अनुदान मिलेगा। उत्तर प्रदेश में एम एस एम ई एक्ट लागू हो गया जिसमें उद्योगों की स्वीकृति मात्र 72 घंटे में मिल जायेगी इसके बाद 900 दिन तक उद्यमी को किसी भी विभाग से अनुमति लेने की आवश्यकता नही है। इस अधिनियम को लागू करके वित्तीय वर्ष में 15 लाख नये रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 2020–21 के बजट में लघु एवं कुटीर उद्योगों के लिए अनेक नई योजनाएं चालू की तथा उनके लिए 100 करोंड़ की धनराशि प्रस्तावित की गई हैं।

उत्तर प्रदेश का औद्योगिक दृष्टि से महत्व

भारत का औद्योगिक विकास में उत्तर प्रदेश का औद्योगिक दृष्टि से निम्नलिखित महत्व हैंः–

1. उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख चीनी उत्पादक राज्यों में से एक हैं। हथकरघा उद्योग यहाँ का सबसे बड़ा उधोग हैं।
2. 2011 की जनसंख्या के अनुसार प्रदेश में कुल कर्मकारों में से केवल 10 प्रतिशत लोग ही उद्योगों में नियोजित हैं।
3. कुल उद्योगों की संख्या तथा रोजगार सृजन क्षमता के आधार पर उत्तर प्रदेश का देश में पांचवां स्थान हैं।
4. प्रदेश की अर्थव्यवस्था में उद्योग क्षेत्र का प्रतिशत योगदान निम्न हैं–

वर्ष	2000-2001	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08
प्रतिशत	18.7%	16.8%	17.2%	03-04	18.6%	20.6%	21.4%	22.2%

स्त्रोतः– उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की रिपोर्ट।

5. योजना काल में उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास में विनिर्माण क्षेत्र औसत वार्षिक वृद्वि दर निम्न रही–

योजनाएं	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
वर्षिक वृद्वि दर	2-3	1-7	5-7	3-4	9-4	11-8	10-9	4-2	&4-3	5-8	7-7	11-2

स्त्रोतः– यू० पी० हैण्डलूम हथकरघा भवन कानपुर की रिपोर्ट।

6. कानपुर उत्तर भारत का मानचेस्टर कहलाता है यहां सूती वस्त्रों की 14 मीले हैं।
7. 1963 में उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ की स्थापना हुई जिसके अन्तर्गत वर्तमान में 28 चीनी मिले है। राज्य में 80 से अधिक चीनी मिले निजी क्षेत्र में हैं।
8. प्रदेश में काँच के 32 कारखाने तथा 90 कारखाने चूड़ी बनाने के हैं।

उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम स्तर के उद्योगः–उ० प्र० लघु उद्योगों का विकास

उत्तर प्रदेश में लघु उद्योगों का विकास वहाँ पर हुआ जहाँ पर ज्ञान कौशल व कुशल श्रम उपलब्ध है–

	आर्थिक क्षेत्र	लघु उद्योगों की संख्या	निवेश (करोड़ों में)	रोजगार (लाख में)
1.	केन्द्रीय क्षेत्र	14164	1667	3.90
2.	पूर्वी क्षेत्र	179297	1729	6.49
3.	पश्चिमी क्षेत्र	32457	5540	14.15
4.	उत्तर प्रदेश	67518	8636	24.54

स्त्रोतः– कुरूक्षेत्र मासिक पत्रिका 2018।

उ० प्र० में प्रमुख उद्योग तथा केन्द्रों के नाम निम्न हैं–

क्र.	प्रमुख उद्योगों के नाम	केन्द्र का नाम
1.	कालीन एवं दरियां	मिर्जापुर, आगरा, मथुरा, बरेली, अलीगढ़, शाहजहाँपुर, भदोही, सहारनपुर।
2.	कम्बल	नजीबाबाद, मेरठ, आगरा, शाहजहांपुर, अलीगढ़।
3.	रेशमी साड़ियाँ	वाराणसी
4.	हथकरघा सूती वस्त्र	वाराणसी बिलासपुर, मऊ, सन्डीला।
5.	हथकरघा सूती वस्त्र	मेरठ, सिकन्दराबाद, धामपुर।
6.	चिकन का काम	लखनऊ।
7.	जरी और चिकन पर गोटे का काम	लखनऊ।
8.	लकड़ी के खिलौने	लखनऊ, वाराणसी।
9.	लकड़ी का फर्नीचर	बरेली, हाथरस आगरा।
10.	लकड़ी का नक्कासी	सहारनपुर, नगीना।
11.	खेल का सामान	मेरठ, आगरा।
12.	बेत एवं छड़ियाँ	बरेली।
13.	पीतल व मूर्तियाँ	मथुरा, मुरादाबाद।
14.	वर्तनों पर कलई एवं नक्कासी	मुरादाबाद, मिर्जापुर।
15.	पीतल के सरोते चाकू एवं कैंची	अलीगढ़, मथुरा, मेरठ, हाथरस।
16.	लोहे के बांट	सहारनपुर, आगरा।
17.	चूड़ों के उद्योग	फिरोजाबाद
18.	मिटटी के खिलौने	आगरा।
19.	चीनी मिटटी के वर्तन	खुर्जा, गाजियाबाद, लखनऊ।
20.	इत्र	कन्नौज, गाजीपुर, लखनऊ, जौनपुर।
21.	हाथ से कागज बनाना	मथुरा, कालपी, कागजी, सराय।
22.	वाद्य यन्त्र (हरमोनिया, लबला, बांसुरी)	मेरठ,कानपुर,लखनऊ।
23.	बिस्किट	मोदीनगर, आगरा, अलीगढ़।
24.	दियासलाई उद्योग	बरेली, सहारनपुर, इलाहाबाद, मेरठ।
25.	साबुन उद्योग	कानपुर, आगरा, मोदीनगर, गाजियाबाद, मेरठ।
26.	सिगरेट निर्माण	सहारनपुर, गाजियाबाद।
27.	टाँच निर्माण	लखनऊ।
28.	औषधि निर्माण	कानपुर, झांसी, लखनऊ।
29.	नल के पाइप	इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ।
30.	गुड़ उद्योग	सीतापुर, बरेली, मुजफ्फरनगर।

स्त्रोतः– भारतीय आर्थिक समस्याओं के अन्तर्गत उ० प्र० में औद्योगिक विकास– वी.सी सिन्हा पेज नं० 417

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन हेतु चलाये जा रहे प्रमुख कार्यक्रम

1. 1978-1979 से प्रत्येक जिले में जिला उद्योगों केन्द्र की स्थापना की गयी जिनकी सहायता से अनेक सरकारी योजनाएं संचालित हैं।

2. 3 अक्टूबर 2006 से लागू सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के तहत पंजीकरण समाप्त कर दिया गया हैं।
3. प्रदेश के सफल एवं उत्कृष्ट लघु उद्यमियों हेतु अगस्त 2009 से पुरस्कार योजना शुरू की गयी।
4. प्रति वर्ष 8 से 15 दिसम्बर तक अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह मनाया जाता हैं।
5. 2007 से उत्तर प्रदेश सूक्ष्म एवं लघु उद्योग तकनीकी उन्नयन योजना चलायी जा रही हैं।
6. भारी लघु व मध्यम उद्योगों को सुविधाजनक बनाने हेतु राज्य में 'निवेश मित्र योजना 2009 संचालित हैं। एकल खिड़की व्यवस्था से निवेश स्वीकृति का जल्द निस्तारण।
7. हथकरघा एवं पावरलूम बूनकरों के लिए 2002 में घोषित जनश्री बीमा योजना 2003–04 से लागू है जिसमें 18 से 60 वर्ष के बुनकरों को लाभ मिलेगा।
8. भारत सरकार द्वारा महात्मा गाँधी बुनकर बीमा योजना 2008–09 से लागू है जिसमें 15 से 59 वर्ष के बुनकरों को बीमा सुरक्षा प्रदान की गयी हैं।
9. हथकरघा बुनकरों लिए मा० काशीराम हथकरघा पुरस्कार योजना 2008–09 में शुरू हुई जिसमें तीन बुनकरों को क्रमशः 25.21.18 हजार रूपये का पुरस्कार दिया जाता हैं।
10. लघु उद्योग के विकास हेतु कई योजनाएं संचालित है जैसे– त्वरित निर्यात प्रोत्साहन या लघु उद्योग कलस्टर विकास योजना, लघु उद्योग तकनीकी उन्नयन योजना, उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम एकीकृत अवस्थापना विकास केन्द्र योजना, लघु उद्यमी पुरस्कार योजना शिल्पियों को प्रशिक्षण एवं उद्योग बन्धु योजना आदि।

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में लघु एवं कुटीर उद्योगों का महत्व हैं–

1. लघु उद्योगों में सुन्दर कलात्मक व टिकाऊ वस्तुओं का उत्पादन होता हैं।
2. पिछड़े क्षेत्रों का आर्थिक विकास में योगदान।
3. कृषको के खाली समय का सदुपयोग।
4. औद्योगिक समस्याओं में कमी तथा रोजगार में कमी।
5. कृषि से जनसंख्या के भार में कमी।
6. आर्थिक सम्पन्नता, सामाजिक जीवन में समानता।

उ० प्र० में लघु एवं कुटीर उद्योगों की समस्याएं

1. नये यन्त्रों, डिजाइनों के लिए शोध की समस्या।
2. परिवहन के साधनों की कमी।
3. प्रबन्ध योग्यता का अभाव।
4. कच्चे माल की समस्या।
5. बड़े उद्योगों से प्रतियोगिता एवं उत्पादन की परम्परागत प्रणाली का होना।

लघु उद्योगों के विकास हेतु सुझाव

1. लघु एवं कुटीर उद्योगों का बड़े उद्योगों के साथ समन्वय होना चाहिए जिससे प्रतियोगिता समाप्त हो सकें।
2. सरकार को लघु उद्योगों को संरक्षण देना चाहिए। तथा समय 2 पर नये अनुसंधान करवाने चाहिए।
3. लघु उद्योगों के लिए दीर्घकालीन ऋृण आसान शर्तो पर उपलब्ध कराने चाहिए।
4. करारोपण करते समय सरकार को उदार नीति अपनानी चाहिए।
5. उत्पादन लागत कम करने हेतु इन उद्योगों को सस्ती दरों पर विद्युत शक्ति उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

निष्कर्ष

वैश्वीकरण तथा उदारीकरण के इस दौर में प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तेजी से उन्नति हो रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी अनेक उद्योगपतियों को निवेश हेतु आमंत्रित कर रहे हैं। जिससे प्रदेश में रोजगार सृजन होगा तथा बढती हुई श्रम शक्ति का सही प्रयोग हो सकेगा।

ग्रामीण युवाओं को न केवल स्वरोजगार के माध्यम से बल्कि विभिन्न उद्योगों की स्थापना के लिए प्रेरित किया जाए ताकि इनकी विभिन्न आवश्यकताएं स्थानीय स्तर पर ही पूरी हो । इससे न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों से होने वाला अनावश्यक पलायन को भी रोका जा सकेगा।

अतः हम उपरोक्त विवेचना से कह सकते हैं कि लघु एवं कुटीर उद्योग परोक्ष रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था व उत्तर प्रदेश के विकास में बहुत सहायक हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1- *भारतीय अर्थव्यवस्था – रूद्र एवं दत्त*
2- *औद्योगिक अर्थशास्त्र – डॉ० आर०एस० कुलश्रेष्ठ*
3- *उत्तर प्रदेश वार्षिक – श्री भगवान स्वरूप कटियार*
4- *भारतीय आर्थिक समस्याएं – श्री वी. सी. सिन्हा*
5- *भारतीय उद्योगों का संगठन एवं प्रबन्ध – पदमाकर*
6- *कुटीर एवं लघु उद्योग – रमाशंकर श्रीवास्तव*
7- *सांख्यिकी पत्रिका शाहजहांपुर – जिला अर्थ एवं साख्यधिकारी*
8- *भारतीय अर्थशास्त्र विकास की समस्याएं – दमस चटर्जी*
9- *अर्थव्यवस्था अवलोकन पत्रिका– जनवरी 2011*
10- *योजना मासिक पत्रिका – सितम्बर 2011*
11- *कुरूक्षेत्र मासिक पत्रिका – अक्टूबर 2014*
12- *कुरूक्षेत्र मासिक पत्रिका – अक्टूबर 2018*
13- *यूपिका हैण्डलूम : यू०पी० हैण्डलूम हथकरघा भवन जी०टी० रोड कानपुर उ० प्र० अक्टूबर 1991*
14- *बुनकर वाहिनी मासिक : उत्तर प्रदेश हथकरघा उत्पादक संघ शाखा मेरठ जनवरी 1990*
15- *ग्रामोद्योग पत्रिका*
16- *दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला बरेली मण्डल*
17- *दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण*
18- *www.upsic.in*